[2014] 13 एस. सी. आर. 675

यू. पी. हिंदी साहित्य सम्मेलन

बनाम

यू. पी. राज्य

(1997 का दीवानी अपील संख्या- 459)

सितंबर 04, 2014

[आर.एम. लोधा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, मदन बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और एस.ए. बोबडे, न्यायामूर्तिगण]

भारतीय संविधान, 1950-भाग XVII; अनुच्छेद 345 और 347-भाग XVII की संवैधानिक योजना-अनुच्छेद 345 और 347 की दायरा और विषय-चर्चा की गई।

भारतीय संविधान, 1950-भाग XVII; अनुच्छेद 345 और 347-1951 अधिनियम को राज्य विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों और अन्य मामलों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए 0 का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था-इसके बाद, 1951 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए 1989 का संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। धारा 2 के बाद धारा 3 डाला गया था। 1951 के अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए उद्देश्यों के लिए उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रदान किया गया। क्या यू. पी. विधान सभा के लिए 1989 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करना संवैधानिक था, जब उसने 1951 में अनुच्छेद 345 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था- मानाः केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट

रूप से या अलग से उल्लेख किया गया था और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान ने राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को बंद कर दिया है-अनुच्छेद 345 में कुछ भी नहीं है। धारा 3 न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में उर्दू को सात निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली विवादित अधिसूचना असंवैधानिक थी-उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 -धारा 3-उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

माना कि 1.1. केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को रोकता है। संविधान के अनुच्छेद 345 में कुछ भी हिंदी के अलावा राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने से नहीं रोकता है। [कंडिकायें 26 और 27] [693-डी-ई]

1.2. अनुच्छेद 345 में "मई" शब्द का उपयोग महत्वहीन नहीं है। यह इंगित करता है कि राज्य को राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं को अपनाने का विवेकाधिकार है। हिन्दी भी। इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा जितनी बार उचित लगे उतनी बार किया जा सकता है। इस तरह की विधायी शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 347 में है। [पैरा 31] [695-डी-ई]

1.3. अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। ये दोनों प्रावधान किसी भाषा को आधिकारिक भाषा

के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने या निर्देश जारी करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 347 में "राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो", राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 345 के तहत भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो राज्य में उपयोग में है। अनुच्छेद 347 की आवश्यकता को राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। [पैरा 37] [697·एफ·एच; 698·ए·बी]

1.4. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है। कानून और भाषा दोनों अपने विकास के तरीके में जैविक हैं। भारत में ये विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों की वैध आकांक्षाओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हो रहे हैं। भारतीय भाषा के कानून कठोर नहीं हैं, बल्कि अनुकूल हैं-जिसका उद्देश्य भाषाई धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित करना है। न तो 1989 के संशोधन अधिनियम में धारा 3 को शामिल करना और न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में उर्दू को सात उद्देश्यों के लिए दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली आक्षेपित अधिसूचना असंवैधानिक है। [कंडिकों 43,44] [701-सी-एफ]

श्री नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण (**1975) 2 एस. सी. सी. 671-लागू नही होती।**

श्री बी. शिव राव (परियोजना समिति के अध्यक्ष) द्वारा "भारत के संविधान का निर्माण-एक अध्ययन"; भारतीय संविधान-**ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा एक राष्ट्र की आधारशिला, नौवां प्रभाव, 2005;** भारत का संवैधानिक कानून-**एच. एम. सीरवई द्वारा** एक आलोचनात्मक टिप्पणी **(चौथा संस्करण);** भारत के संविधान पर टिप्पणी, **खंड 9,2011 आचार्य डी. दुर्गा**

दास बसु द्वारा; टी. के. टोपे, तीसरा संस्करण, 2010 और "भाषा नीति और भाषाई संस्कृति"। भाषा नीति का परिचयः**हेरोल्ड शिफमैन** द्वारा सिद्धांत और विधि **(2006)- संदर्भित।**

वाद कानून संदर्भः

(1975) 2 एस.सी.सी. 671 लागू नहीं होती पैरा 29

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1997 का दीवानी अपील संख्या- 4590

इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की लखनऊ पीठ द्वारा 1989 की दीवानी विविध याचिका संख्या- 10313 में दिनांक 16.08.1996 के पारित निर्णय और आदेश से

श्याम दीवान, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. आई. बी. गौर, एस. एस. नेहरा, नीरज दत्त गौर, पीयूष शर्मा, विक्रमजीत बनर्जी, राकेश कुमार, मेरुसागर सामंतरी, इम्तियाज अहमद और सुश्री नगमा इम्तियाज (मेसर्स इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स के लिए), अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

डॉ. राजीव धवन, आर. पी. मेहरोत्रा, विभु तिवारी, अभिनव के. मलिक, आशुतोष के. शर्मा, कमलेंद्र मिश्रा, मोहम्मद इरशाद हान इफ, विश्वजीत सिंह, ए. एस. पुंडिर, अरिजीत सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

इस न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा सुनाया गया।

आर. एम. लोधा, भारत के मुख्य न्यायाधीश 1. 12.11.1951 को उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-XXVI वर्ष 1951) (संक्षेप में, '1951 अधिनियम') राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुआ और लागू हुआ। 1951 अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा हिंदी में 27.09.1951 को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद

द्वारा 29.09.1951 को पारित किया गया था। इसे 05.11.1951 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई। 1951 अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों और अन्य मामलों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाया गया है।

2. 1951 के अधिनियम की धारा 2 निम्नानुसार हैः

2. हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी। –संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देवनागरी लिपि में हिंदी, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी, जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित के संबंध में उपयोग की जाने वाली भाषा होगीः.

(ए) (i) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश

(ii) भारत के संविधान के तहत या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, नियम विनियम और उप-कानून, और

(बी) राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए; और खंड (ए) और (बी) में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं।

1969 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 द्वारा उपरोक्त धारा 2 में एक परंतुक जोड़ा गया था। "बशर्ते कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में, राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग की अनुमति दे सकती है।

3. 07.04.1982 को, एक अध्यादेश जिसे उत्तर प्रदेश अधिकारिक भाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1982 राज्यपाल द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अध्यादेश की धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि 1951 के अधिनियम में, धारा 2 के बाद, निम्नलिखित धारा (धारा 3 मानी गई) को जोड़ा जाएगाः उर्दू भाषी लोगों के हित में, उर्दू भाषा का उपयोग हिंदी के अलावा दूसरी भाषा के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

अध्यादेश की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि मूल अधिनियम में, अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई धारा 3 के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगीः

1. जनता के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उर्दू में मनोरंजक आवेदन।

2. पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए उर्दू में दस्तावेज़ों की एक हिंदी प्रति प्राप्त करना।

3. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन।

4. महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन।

5. उर्दू में राजपत्र का अनुवाद।

4. उपरोक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश अधिकारिक भाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। (1983 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश 44)। 1983 के यू. पी. अध्यादेश की संवैधानिकता को वर्तमान अपीलार्थी यू. पी. हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1984 की रिट याचिका संख्या- 285 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष रखा गया था। इस रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अलग-अलग निर्णयों द्वारा खारिज कर दिया था।

5. 07.10.1989 को, उत्तर प्रदेश अधिकारिक भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का यू. पी. अधिनियम) (संक्षेप में, "1989 संशोधन अधिनियम") लागू हुआ। 1951

के अधिनियम में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा 1989 संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 3 को 1951 के अधिनियम की धारा 2 के बाद जोड़ा गया था, जिसमें उर्दू भाषा को ऐसे उद्देश्यों के लिए दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रदान किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

6. राज्य को प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार उर्दू को निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, राज्य सरकार ने निम्नलिखित सात उद्देश्यों के लिए उर्दू भाषा के उपयोग को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी कीः

1. उर्दू में मनोरंजक याचिकाएं और आवेदन और उर्दू में उनके जवाब,

2. पंजीकरण कार्यालय द्वारा उर्दू में लिखे गए दस्तावेज़ प्राप्त करना,

3. उर्दू में भी महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन,

4. उर्दू में भी सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेश और परिपत्र जारी करना,

5. उर्दू में भी महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का प्रकाशन,

6. राजपत्र के उर्दू अनुवाद का भी प्रकाशन,

7. उर्दू में महत्वपूर्ण साइनपोस्टों की प्रदर्शनी।

7. अपीलार्थी, उत्तर प्रदेश साहित्य (1997 दीवानी अपील संख्या 459) जिसने उत्तर प्रदेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 1984 की रिट याचिका संख्या 285 दायर की थी। 1983 के अध्यादेश संख्या-44 ने 1989 के संशोधन

अधिनियम और दिनांक 07.10.1989 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की।

8. इस रिट याचिका की सुनवाई खंड पीठ ने की थी जिसमें शामिल थे, एस. एन. सहाय और डी. के. त्रिवेदी, न्यायमूर्तिगण

9. एस. एन. सहाय, न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में कहा कि 1989 का संशोधन अधिनियम और रिट याचिका में आक्षेपित अधिसूचना अधिकार से बाहर थे और निरस्त किए जाने योग्य थे। हालाँकि, उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के प्रावधानों के अनुसार उर्दू के संबंध में भविष्य में कोई कानून बनाने से रोका नहीं जाएगा।

10. दूसरी ओर, डी. के. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति एस. एन. सहाय, न्यायमूर्ति के दृष्टिकोण से सहमत नही थे। उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा कि 1989 का संशोधन अधिनियम और रिट याचिका में आक्षेपित अधिसूचना संवैधानिक बुराई से ग्रस्त नहीं है और रिट याचिका खारिज होने योग्य है।

11. सदस्यों के बीच मतभेद को देखते हुए पीठ ने निम्नलिखित प्रश्नों को तीसरे न्यायाधीश को उनकी राय के लिए भेजने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का निर्देश दियाः

1. क्या आक्षेपित अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 345 के अर्थ के भीतर एक वैध विधान कहा जा सकता है?

2. क्या आक्षेपित अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है?

3. क्या आक्षेपित अधिनियम और आक्षेपित अधिसूचना वैध और संवैधानिक हैं या अधिकार से बाहर हैं?

12. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तब मामले को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के लिए तीसरे न्यायाधीश, बृजेश कुमार, न्यायमूर्ति (उस समय उनके स्वामी के रूप में) के पास भेजा।

13. बृजेश कुमार, न्यायमूर्ति ने उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दियाः

(1) कि राज्य में उपयोग के लिए किसी दूसरी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए कानून बनाते समय, राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के प्रावधानों को एक साथ पढ़कर उन पर विचार करना होगा; तथापि, आक्षेपित अधिनियम 1984 की रिट याचिका सं. 285 में खंड पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वैध विधान है।

(2) आक्षेपित अधिनियम अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं है।

(3) प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न सं. (1) और (2), मुझे लगता है कि आक्षेपित अधिनियम के साथ-साथ अधिसूचना भी वैध और संवैधानिक है।

14. तीसरे न्यायाधीश द्वारा दिए गए उत्तरों के आलोक में, मामला रिट याचिका पर उचित आदेश के लिए खंड पीठ के समक्ष रखा गया था।

15. खंड पीठ ने अपने दिनांक 16.08.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, रिट याचिका इस प्रकार हैः

विद्वान तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, माननीय बृजेश कुमार को ध्यान में रखते हुए, यू. पी. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, I989 (1989 का यू. पी. अधिनियम No.28) को यू. पी. राजभाषा अधिनियम, 1951 में धारा 3 जोड़ने को अंतर-अधिकार माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आक्षेपित अधिनियम

अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं है। आक्षेपित अधिनियम के साथ-साथ अधिसूचना को वैध और संवैधानिक माना जाता है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

16. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 16.08.1996 के निर्णय और आदेश से व्यथित वर्तमान अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय द्वारा 27.01.1997 को अनुमति दी गई थी।

17. 02.09.2003 को, अपील को सुनवाई के लिए इस न्यायालय की 2 न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने महसूस किया कि विवाद की प्रकृति और मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, यह उचित था कि मामले की सुनवाई 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

18. यह तब था जब मामले को 3-न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 29.10.2003 को सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन, न्यायालय की राय थी कि अपील की सुनवाई 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 की व्याख्या के बारे में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इस तरह से अपील हमारे सामने आई है।

19. संविधान का भाग XVII आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसके चार अध्याय हैं। अध्याय I संघ की राजभाषा से संबंधित है, अध्याय II, अध्याय III और अध्याय IV क्रमशः क्षेत्रीय भाषाओं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और विशेष निर्देश से संबंधित है।

20. यहाँ संविधान के भाग XVII के संबंध में प्रमुख लेखकों के विचारों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा, प्रमुख लोगों के विचारों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित है। आमतौर पर यह माना जाता है कि संविधान सभा में सबसे गहरा विवाद आधिकारिक भाषा के संबंध में था। श्री बी. शिव राव (परियोजना समिति के अध्यक्ष) ने "द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन-ए स्टडी" में लिखा दर्ज हैः

> “इस मुद्दे ने इतनी गर्मी पैदा की और इतनी हिंसक भावनाओं को जन्म दिया कि शुरू से ही इसे विधानसभा में सीधी चर्चा से बाहर रखना आवश्यक महसूस किया गया। नेताओं ने सामान्य समझौते के आधार पर इसे निपटाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अक्सर ऐसा लगता था कि कोई समझौता संभव नहीं हो सकता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंत तक किसी तरह का समझौता नहीं हो सका था। ”
>
> के अध्याय 26 में इस खंड में, इसे आगे दर्ज किया गया हैः
>
> भाषा के मुद्दे पर भावनाएं लगभग संविधान सभा के उद्घाटन के बाद से ही विकसित हुईं। हालाँकि, इस समय हिंदी बनाम उर्दू या हिंदी बनाम हिंदुस्तानी विवाद नहीं उठाया गया था; इस बात पर आम सहमति थी कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा का नाम हो सकता है। जब प्रक्रिया के नियमों पर एक समिति के गठन के सवाल पर चर्चा की गई, तो आर. वी. धुलेकर ने एक संशोधन पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि समिति को अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी में नियम बनाने चाहिए। सभापति ने उनसे अंग्रेजी में बोलने का अनुरोध किया, क्योंकि कई सदस्य हिंदुस्तानी नहीं समझ सकते थे; लेकिन धुलेकर ने न केवल हिंदुस्तानी में बोलने पर जोर दिया, बल्कि यह टिप्पणी की कि जो हिंदुस्तानी नहीं जानते थे, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं था और वे विधानसभा के सदस्य बनने के योग्य नहीं थे। सभापति ने संशोधन को अनुचित बताते हुए चर्चा को संक्षिप्त कर दिया और इसे

प्रतिबंधित कर दिया। सभी आगे की चर्चा '; लेकिन जब समिति की रिपोर्ट चर्चा के लिए आई तो इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया गया। समिति ने सिफारिश की कि विधानसभा में कामकाज हिंदुस्तानी (हिंदी या उर्दू) या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष को इन भाषाओं से अपरिचित किसी भी सदस्य को अनुमति देने की अनुमति दी गई थी। विधानसभा को अपनी मातृभाषा में संबोधित करें। विधानसभा के आधिकारिक अभिलेख उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में रखे जाने थे।

21. भारत के संविधान के निर्माण के चौथे भाग में दस्तावेज़, चुनने, अध्याय 13 राजभाषा से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है कि न तो संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे और न ही मसौदा समिति द्वारा तय किए गए संस्करण में आधिकारिक भाषा से संबंधित कोई प्रावधान था, लेकिन उनमें केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं में उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के बारे में प्रावधान थे। प्रारूप संविधान पर सामान्य चर्चा के दौरान भाषा का मुद्दा प्रमुखता से उठा और बहस के दौरान जो तीखे मतभेद विकसित हुए, उससे पता चलता है कि इस प्रश्न ने किस हद तक भावना पैदा की थी। अगस्त, 1949 के अंत में मुंशी और गोपालस्वामी अय्यंगार ने संविधान के मसौदे में शामिल करने के लिए समझौते के प्रावधानों का विस्तृत मसौदा तैयार किया। प्रारूप समिति द्वारा संशोधित मुंशी और गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा तैयार आधिकारिक भाषा पर मसौदा प्रावधानों में चार अध्याय थे, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा आदि और विशेष निर्देश।

22. भारतीय संविधान में ग्रैनविल ऑस्टिन-एक शब्द की आधारशिला ने मुंशी-अयंगर सूत्र को आधे-अधूरे समझौते के रूप में वर्णित किया है। उनका कहना है कि यह उन विचारों के बीच एक समझौता था जो आसानी से सुलझा नहीं सकते थे। इस सूत्र के पीछे दो बुनियादी सिद्धांत थे, एक "हमें पूरे भारत की आम भाषा के रूप में भारत की भाषाओं में से

एक का चयन करना चाहिए"। दूसरा सिद्धांत यह था कि संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों को भारतीय अंकों के अखिल भारतीय रूपों के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। " विधानसभा के सदस्यों ने मुंशी-अयंगर सूत्र के पक्ष में मतदान किया।

23. एच. एम. सीरवई ने भारत के संवैधानिक कानून में एक आलोचनात्मक टिप्पणी (चौथा संस्करण) में भी एक संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दिया है भाषा का मुद्दा जो संविधान के मसौदे पर चर्चा के दौरान उठा। एच. एम. सीरवई का कहना है कि हमारे संविधान में संघ को दिए गए स्थान को ध्यान में रखते हुए, संघ की आधिकारिक भाषा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। एक ओर अंग्रेजी और हिंदी और दूसरी ओर अनुसूची VIII में उल्लिखित अन्य भाषाओं के बीच अंतर बताते हुए विद्वान लेखक कहते हैंः

> अंग्रेजी विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक वास्तविक माध्यम था और है। संविधान और राजभाषा अधिनियम ने भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग जारी रखा है। इसलिए, ऐतिहासिक कारणों और स्पष्ट संवैधानिक और विधायी प्रावधानों के कारण अंग्रेजी अपने आप में एक वर्ग में खड़ी है। हिंदी भी अपने आप में एक स्थान रखती है। यह भारत संघ की आधिकारिक भाषा है और संविधान में विचार किया गया है कि इसे धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान लेना चाहिए। इसलिए हिंदी भी अपने आप में एक वर्ग में है। लेकिन अन्य भाषाओं का उल्लेख अनुसूची VIII में किया गया है। एक अलग पायदान पर खड़ा है। अंग्रेजी को एक माध्यम के रूप में बनाए रखना उचित है और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को ऊपर बताए गए कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी के लिए किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के प्रतिस्थापन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि लोगों के बड़े समूहों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषाएँ होंगी जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

बनने में सक्षम हैं। क्योंकि शहर में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, मलयालम और उर्दू है, अगर चयन का सिद्धांत यह है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो दूसरों को छोड़कर इनमें से एक या अधिक भाषाओं के चयन को शिक्षा के माध्यम के रूप में उचित ठहराना मुश्किल होगा।

24. आचार्य डॉ. दुर्गा दास बसु, पर अपनी टिप्पणी में भारत का संविधान, खंड 9,2011, "एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता" उप-शीर्षक के तहत भाग XVII पर विचार करते हुए कहता है कि संविधान निर्माता एक भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करने में विफल रहे और संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह मुख्य रूप से विविध दावों के बीच एक समझौता है। डॉ. बसु ने तब कहा कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि (ए) संघ के लिए एक "आधिकारिक भाषा" (अनुच्छेद 343-344); (बी) राज्यों के लिए क्षेत्रीय आधिकारिक भाषाएँ (अनुच्छेद 345-347); और (सी) आधिकारिक भाषा (ए) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए और (बी) केंद्र और राज्य स्तर पर विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, उप-कानूनों के लिए है। डॉ. बसु ने अपने ग्रंथ में टी. के. टोपे * द्वारा भारत के संवैधानिक कानून का उद्धरण दिया है, जिसमें लेखक ने कहा है कि संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है।

25. अब दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 345 और 347 की ओर मुड़ने का समय आ गया है, जो इस मुद्दे पर विचार के लिए पड़े हैं, क्या यह संवैधानिक है उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत 1951 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के बाद 1989 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उर्दू को दूसरी आधिकारिक

भाषा घोषित करने के लिए। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान का निवेदन है कि हिंदी भाषा के विशेष संवैधानिक दर्जे को ध्यान में रखते हुए, जहां किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है, दो बातों का पालन करना आवश्यक है (एक) राज्य विधानमंडल हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने से वंचित है और (दो) राज्य विधानमंडल किसी अन्य आधिकारिक भाषा को अपनाने से वंचित है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क इस आधार पर आधारित है कि संविधान का भाग XVII आधिकारिक भाषा के संबंध में पूर्ण योजना का गठन करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार भाग XVII की दो प्रमुख विशेषताएं हैंःहिंदी भाषा को विशेष दर्जा और भाषा के संवेदनशील और संभावित विभाजनकारी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सौंपे गए संतुलन की विशेष भूमिका।

26. श्री श्याम दीवान के तर्क से जो तार्किक रूप से मिलता है वह यह है कि अनुच्छेद 345 का पाठ राज्य विधानमंडल को दो विकल्प देता है, एक, राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी एक या अधिक भाषाओं को अपनाना (विकल्प 1) और दूसरा, हिंदी (विकल्प 2) और एक बार विकल्प 2 का प्रयोग करने के बाद, राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि श्री श्याम दीवान के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि "या" शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि विकल्प 1 राज्य के विधानमंडल के लिए केवल तभी उपलब्ध होगा जब यह विकल्प 2 के लिए नहीं जाता है। एक बार जब राज्य विधानमंडल विकल्प 2 का प्रयोग कर लेता है और हिंदी को राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना लेता है, तो यह विकल्प 1 के मार्ग पर नहीं जा सकता है। हमें विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। केवल इसलिए कि हिंदी का स्पष्ट रूप से या अलग से उल्लेख किया गया है और इसे राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है, हमें नहीं लगता कि संविधान राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी अन्य

भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के राज्य विधानमंडल के विकल्प को रोकता है।

27. हमारे विचार में अनुच्छेद 345 में ऐसा कुछ भी नही है, जो हिन्दी के अलावा राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषाओं दूसरी अधिकारिक भाषा घोषित करने से रोकता है। यह केवल अनुच्छेद 345 में निहित प्रावधान को विकृत करने की कीमत पर हो सकता है। "या" "हिंदी" "से पहले आने वाले शब्द का महत्व हिंदी के" "उपयोग में" "होने की आवश्यकता को समाप्त करना है, जबकि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए" "उपयोग में" "होने की आवश्यकता को पूरा करना होगा। "हिंदी के लिए इस आवश्यकता को पूरा करने का उद्देश्य राज्यों में हिंदी को अपनाना था। इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता है कि विशेष राज्य विधानमंडल को राज्य के भीतर अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने में अपनी शक्ति का त्याग करना चाहिए। अनुच्छेद 345 में अलग से हिंदी का उपयोग करने का उद्देश्य राज्यों में हिंदी को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है, चाहे हिंदी किसी विशेष राज्य में उपयोग में हो या नहीं। कोई अन्य निर्माण अनुच्छेद 345 संविधान द्वारा अपनाए गए भाषा समझौते में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगा।

28. संविधान का भाग XVII जैसा कि इसकी योजना से पता चलता है, समायोजनात्मक है। आखिरकार, भाषा नीतियाँ निर्मित होती हैं और वे समय के साथ बदलती रहती हैं।

29. अनुच्छेद 345 की स्पष्ट भाषा, जो राज्य विधानमंड को राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को अपनाने के लिए कानून बनाने के लिए विधानमंडल इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 की साधारण भाषा से एक अलग इरादा

दिखाई नहीं देता है। हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है और वह शक्ति समाप्त हो जाती है यदि राज्य विधानमंडल हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है। हमारे विचार में, राज्य विधानमंडल समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 345 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। हमें ऐसा नहीं लगता कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के बाद, राज्य विधानमंडल के पास अनुच्छेद 345 के तहत कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। नसीरुद्दीन 1 में इस न्यायालय के फैसले में अनुच्छेद 345 के निर्माण के उद्देश्य के लिए लागू नही होता।

30. हम थोड़ी देर बाद "विषय" अभिव्यक्ति पर चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि कई राज्य विधान मंडल हैं जिन्होंने हिंदी के अलावा बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसी अन्य आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं को अपनाया है। दिल्ली ने हिंदी के अलावा पंजाबी और उर्दू को अन्य आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में भी अपनाया है। जाहिर है, यह संभव नहीं होता लेकिन संवैधानिक अनुमति के लिए होता।

31. पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति “राज्य में उपयोग में आने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को अपनाए” के संदर्भ में अनुच्छेद 345 में अलग से हिन्दी का उल्लेख करने की स्थिति अनुच्छेद 357 के संदर्भ में हिंदी को बढावा देने और फैलाने के लिए है, अनुच्छेद 345 पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति के संदर्भ में "राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी एक या अधिक भाषाओं को अपनाना" अनुच्छेद 351 के संदर्भ में हिंदी को बढ़ावा देना और फैलाना है, हालांकि यह राज्य में लोगों द्वारा बोली या उपयोग नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए राज्य में

उपयोग की जाने वाली भाषाओं की किसी भी संख्या को अपनाने में सक्षम बनाता है। यह आवश्यक नहीं है कि राज्य सरकार से उस ओर से मांग की जानी चाहिए या यदि कोई मांग है, तो राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कानून नहीं बना सकता है। यह अनुच्छेद 345 और 347 के बीच की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। यदि किसी विशेष राज्य में हिंदी का उपयोग किया जाता है तो यह हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की राज्य की शक्ति या विवेकाधिकार को नहीं रोकता है बशर्ते कि ऐसी भाषा उस राज्य में 'उपयोग में' हो। अनुच्छेद 345 में "मई" शब्द का प्रयोग बिना महत्व के नहीं है। यह इंगित करता है कि राज्य को इसे अपनाने का विवेकाधिकार राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाएँ और इसी तरह हिंदी भी है। इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा जितनी बार उचित लगे उतनी बार किया जा सकता है। इस तरह की विधायी शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध किसी दी गई स्थिति में अनुच्छेद 347 में है जिसे हम कुछ और चर्चा के बाद समझाएंगे।

32. संविधान के भाग XVII का शीर्षक "राजभाषा" है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि श्याम दीवान एक पूर्ण संहिता के समान संविधान का एक स्व-निहित हिस्सा है। उनका निवेदन है कि भाग XVII के प्रावधान आधिकारिक भाषा के संबंध में एक पूर्ण योजना का गठन करते हैं। हम इस हद तक विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं। उनका यह कहना भी सही है कि हिंदी भाषा को विशेष दर्जा प्राप्त है और विशेष रूप से भाग XVII में। इस संबंध में अनुच्छेद 343 (1), 344 (2) (ए), 345,346 परंतुक, 348 (2) और 351 का उल्लेख सही किया गया है। संविधान में उपरोक्त प्रावधान, हमारे विचार में, हिंदी के लिए बड़े संवैधानिक चार्टर का निर्धारण करते हैं, लेकिन यह स्थिति किसी भी तरह से अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि जहां किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है, राज्य

विधानमंडल किसी अन्य आधिकारिक भाषा को अपनाने से वंचित है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 345 में हिंदी के अलावा राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य आधिकारिक भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने पर कोई रोक नहीं है।

33. यह सच है कि भाग XVII राष्ट्रपति की भूमिका को निर्दिष्ट करता है (या उस मामले के लिए, 'केंद्र सरकार') कई प्रावधानों के तहत। राष्ट्रपति एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा की मांग का जवाब दे सकते हैं जहां अनुच्छेद 347 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह निर्देश देने से पहले कि किसी विशेष भाषा को पूरे राज्य या राज्य के किसी हिस्से में ऐसे उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि "किसी राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए करना चाहता है। "अनुच्छेद 350 बी एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में मूल्यांकन कर सकते हैं। हालाँकि, हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि संविधान के भाग XVII में व्यवस्था यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि राज्य क्रमिक रूप से कई आधिकारिक भाषाओं की मांगों को स्वीकार न करें और यह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति (केंद्रीय कार्यकारी) के पास आरक्षित है।

34. अनुच्छेद 345 में आने वाली अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 346 और 347" के प्रावधानों के अधीन "अनुच्छेद 345 को अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन नही बनाती है "के अधीन". अभिव्यक्ति का प्रभाव यह है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए मौजूदा, यदि कोई हो, निर्देशों के अधीन है, जब राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

एक बार राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अनुच्छेद 347 के तहत, राज्य विधानमंडल के लिए किसी भी तरह से इस तरह के निर्देश के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ किसी भी तरह से टकराव में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य की पूर्ण शक्ति केवल इस हद तक सीमित है। ऊपर उल्लिखित सीमित सीमा को छोड़कर, यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 347 के अधीन या अधीनस्थ है। भाग XVII को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और हमारे विचार में, अनुच्छेद 345 और 347 का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि इसे संघीय संरचना और इसी तरह इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

35. अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति..... के अधीन अभिव्यक्ति के आधार पर अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश के विरुद्ध प्रतिबंधित है। ऐसे निर्देश के अभाव में, राज्य विधायिका को अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से किसी भी तरह से रोका नही जाता है।

36. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में राज्य विधानमंडल के लिए कोई प्रतिबंध, संयम या बाधा नहीं है।

37. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अनुच्छेद 345 राज्य के विधायिका की शक्ति से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। ये दो प्रावधान किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने या निर्देश जारी करने के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 347 में "राज्य की

आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो", राज्य विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 345 के तहत भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो राज्य में उपयोग में है। हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 347 की आवश्यकता को राज्य विधायिका के लिए अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में पढ़ा जा सकता है। हम डी. के. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, "*एकमात्र सीमा लागू की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधायिका पर यह है कि उक्त भाषा राज्य में उपयोग में होनी चाहिए और आगे यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 347 के तहत कोई निर्देश जारी किया गया है तो उसका एक बाध्यकारी प्रभाव होगा। "*

38. एक या अधिक भाषाओं को अपनाने का मानदंड, हिंदी के अलावा, राज्य में ये भाषाएँ "राज्य में उपयोग में" होनी चाहिए। इस मानदंड को उस समय पूरा किया जाना चाहिए जब राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यदि राज्य में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है तो राज्य विधानमंडल किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपना सकता है। हालाँकि, राज्य विधानमंडल के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने में कोई बाधा नहीं है, भले ही कर्नाटक में हिंदी "उपयोग में" न हो। इसका कारण भाषाई मुद्दे पर संवैधानिक समझौते में पाया जाता है, पूरे भारत में हिंदी के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए हिंदी के लिए बड़ा संवैधानिक चार्टर जारी किया गया।

39. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि अध्याय भाग XVII का II राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल और केंद्रीय स्तर पर संघ कार्यपालिका (राष्ट्रपति) को

शामिल करते हुए एक अद्वितीय द्विभाजन का निर्माण करता है। यह किसी राज्य में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए दो मार्ग प्रदान करता है; (ए) राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा अपनाया जाना; और (बी) भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक निर्देश। ये दोनों मार्ग पूरक हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना सही है कि भारत का संविधान किसी राज्य में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए दो मार्ग प्रदान करता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालांकि, उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां राज्य विधानमंडल ने किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है, और किसी अन्य भाषा को मान्यता देने की मांग है जो किसी राज्य की आबादी के एक बड़े अनुपात द्वारा उपयोग की जाती है, संविधान में दूसरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए केवल एक विधि प्रदान की गई है, जो अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति के निर्देश के माध्यम से है, वह पूरी तरह से सही नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 347 का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना सही है कि यदि किसी अन्य भाषा की मान्यता की मांग की जाती है जिसका उपयोग किसी राज्य की आबादी के एक बड़े अनुपात द्वारा किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति के निर्देश के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, वह सही नहीं है कि दूसरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने का यह एकमात्र तरीका है, अगर विद्वान वरिष्ठ वकील का निर्माण स्वीकार किया जाता है, यह राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने में राज्य विधानमंडल की शक्ति को प्रतिबंधित और सीमित करेगा। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति में कटौती, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाव दिया गया है, न तो संवैधानिक रूप से सही है और न ही यह आम तौर पर संविधान के भाग XVII की योजना और अनुच्छेद 345 और 347 के तहत शामिल योजना से आता है। हम स्वयं को विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत नहीं पाते हैं कि ऐसी स्थिति जहां दूसरी आधिकारिक भाषा की मांग है, अनुच्छेद 347 ऐसी मांग का

जवाब देने के लिए संविधान में ज्ञात एकमात्र तरीका है। हमारे विचार में, यह अनुच्छेद 345 और 347 की गलतफहमी है।

40. हमने जो ऊपर कहा है, उसमें हम अपीलकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से सहमत नही है कि चूँकि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक 1989 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणो के कथन में स्पष्ट रुप से दर्ज है कि उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने की मांग समय-समय पर की गई थी, इसलिए आक्षेपित कानून अनुच्छेद 347 में परिकल्पित स्थिथिति को शामिल करता है और इसलिए अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधायी शक्ति का आह्वान करना संवैधानिक रुप से गलत है।

41. अनुच्छेद 350 का एक मात्र पाठ यह दर्शाएगा कि यह एक प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील इस स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं कि राज्य कार्यपालिका नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं को अपना सकती है। जाहिर है, तब राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 345 द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र के संबंध में अपनी संवैधानिक शक्ति के भीतर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने और अधिक आधिकारिक भाषाओं को अपनाने के बाद राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषा को अपनाकर कानून बनाने के लिए होगा। राज्य द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग को अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का निर्देश क्षेत्र पर कब्जा नहीं करता है।

42. संविधान का अनुच्छेद 367 एक व्याख्यात्मक प्रावधान है। अनुच्छेद 367 का खंड (1) इस प्रकार हैः

367. व्याख्या-(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, सामान्य खंड अधिनियम, 1897, अनुच्छेद 372 के तहत उसमें किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन रहते हुए, इस संविधान की व्याख्या के लिए उसी तरह लागू होगा जैसे यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

(2) xxx xxx xxx

(3) xxx xxx xxx

43. संविधान में उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14 का प्रावधान लागू होता है। संविधान की व्याख्या और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य विधानमंडल समय-समय पर अनुच्छेद 345 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हम अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 14 का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि भाग XVII की संवैधानिक योजना में एक अलग इरादा दिखाई देता है। हम पहले ही भाग XVII की संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 345 और 347 के दायरे और दायरे के बारे में बता चुके हैं। जिन कारणों का हमने ऊपर संकेत किया है, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है। यह तर्क संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और अनुच्छेद 345 और 347 से नहीं आता है। हमारे विचार में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाए गए तरीके से अनुच्छेद 345 का अर्थ लगाना अनुचित होगा। ऐसा कहा जाता है कि कानून और भाषा दोनों अपने विकास के तरीके में जैविक हैं। भारत में ये विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों की वैध आकांक्षाओं को स्वीकार

करने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हो रहे हैं। भारतीय भाषा के कानून कठोर नहीं हैं, बल्कि अनुकूल हैं-जिसका उद्देश्य भाषाई धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित करना है।

44. हम मानते हैं, जैसा कि हमें करना चाहिए, कि न तो 1989 के संशोधन अधिनियम के धारा 3 को शामिल करना और न ही उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में सात उद्देश्यों के लिए उर्दू का दूसरी भाषा के रूप में अधिसूचित करने वाली आक्षेपित अधिसूचना असंवैधानिक है।

45. अपील में कोई योग्यता नहीं है और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।

विभूति भूषण बोस अपील खारिज

भाग XVII

343. संघ की आधिकारिक भाषा- (1) संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।

संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह साल की अवधि के लिए, अंग्रेजी भाषा का उपयोग संघ के उन सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जारी रहेगा, जिनके लिए इस तरह के प्रारंभ से तुरंत पहले इसका उपयोग किया जा रहा थाः

बशर्ते कि राष्ट्रपति, उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा और अंकों के देवनागरी रूप के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, संसद पंद्रह वर्ष की उक्त अवधि के बाद, कानून द्वारा उपयोग के लिए प्रावधान कर सकती है -

(ए) अंग्रेजी भाषा, या

(बी) अंकों का देवनागरी रूप,

ऐसे प्रयोजनों के लिए जो कानून में निर्दिष्ट किए जाएं।

344. राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति।

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जो आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगा।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को

(ए) संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग के बारे में सिफारिशें करे।

(बी) संघ के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध;

(सी) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा;

(डी) संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप;

(ई) संघ की राजभाषा और संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए भाषा और उनके उपयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

(3) खंड (2) के तहत अपनी सिफारिशें करते समय आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति और लोक सेवाओं के संबंध में गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों को ध्यान में रखेगा।

(4) तीस सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाएगा, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य परिषद के सदस्य होंगे जिन्हें क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से चुना जाएगा।

(5) खंड (1) के तहत गठित आयोग की सिफारिशों की जांच करना और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय देना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, खंड (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उस रिपोर्ट के पूरे या किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकता है।

345. किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएँ:- अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन और किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उस राज्य में उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकता हैः

बशर्ते कि, जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करता है, तब तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग उस राज्य के भीतर उन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जारी रहेगा, जिसके लिए इसका उपयोग इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के बीच संचार के लिए राजभाषा और संघ:- आधिकारिक प्रयोजनों के लिए संघ में उपयोग के लिए कुछ समय के लिए अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होगीःबशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हों कि हिंदी भाषा ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, तो उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।

347. राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान:-

उस ओर से की जा रही मांग पर राष्ट्रपति, यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा के उपयोग को उस राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को उस राज्य में या उसके किसी हिस्से में उस उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी जो वह निर्दिष्ट करे।

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा:-

(1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है -

(ए) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां,

(बी) आधिकारिक ग्रंथ -

(i) संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनमें संशोधनों के बारे में,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों का, और

(iii) इस संविधान के तहत या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उप-कानून अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, जिसका उस राज्य में प्रमुख स्थान हैःबशर्ते कि इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने राज्य के विधानमंडल में या राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में या उस उपखंड के पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में पेश किए गए विधेयकों या पारित अधिनियमों में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा निर्धारित की है, वहां उस राज्य के राज्यपाल के अधिकार के तहत उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के तहत अंग्रेजी भाषा में उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया :- इस अवधि के दौरान इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष के भीतर, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश या पेश नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के खंड (1) के तहत गठित आयोग की सिफारिशों और उस अनुच्छेद के खंड (4) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद के अलावा ऐसा कोई भी विधेयक पेश करने या ऐसा कोई संशोधन पेश करने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा।

350. शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा: - हर व्यक्ति होगा संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ या राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में, किसी भी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार।

350ए. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं:- यह प्रयास होगा भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण; और

राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350B. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:-

(1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करे जो राष्ट्रपति निर्देशित करे, और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा।

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश:- यह संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना, इसे विकसित करना ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसकी प्रतिभा, हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों में हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके और जहां भी आवश्यक या वांछनीय हो, अपनी शब्दावली के लिए, मुख्य रूप से संस्कृत पर और दूसरी भाषाओं पर, चित्र बनाकर इसे समृद्ध कर सके।

¥ 23.2 भाषा से संबंधित हमारे संविधान के प्रावधानों ने कानूनी व्याख्या के कोई गंभीर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन उन्होंने गंभीर राजनीतिक समस्याएं खड़ी की हैं। भाषा के बारे में विवाद के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन करना इस कार्य के दायरे से बाहर है जिसके परिणामस्वरूप हमारे संविधान के भाग XVII को लागू किया गया। न ही ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि ऑस्टिन ने "भाषा और संविधान-अर्ध-हृदय समझौता" नामक अपने अध्याय में खेल की ताकतों का एक अच्छी तरह से प्रलेखित और ज्वलंत विवरण दिया है। अध्याय अध्ययन का पुनर्भुगतान करता है, लेकिन इसका प्रभाव इस प्रकार बताया जा सकता हैःराजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रीय भाषा का सवाल उठाया। उन्होंने कभी-कभी इसे हिंदी और कभी-कभी हिंदुस्तानी के रूप में वर्णित किया, लेकिन वे ऐसी भाषा दोनों से समझते थे जो न तो संस्कृतकृत हिंदी थी और न ही फारसीकृत उर्दू, बल्कि दोनों का एक सुखद मिश्रण था, जो या तो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी गई थी। हालाँकि भाषा के सवाल पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जब तक कि इसे संविधान सभा पर मजबूर नहीं किया गया। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर एक राष्ट्रीय भाषा की आम मांग थी। लेकिन कठिनाइयाँ तब स्पष्ट हो गईं जब उस माँग को संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तित करना पड़ा। भारतीय लोगों के बीच एकता की आवश्यकता निर्विवाद थी, और अंग्रेजी ने उत्तर के लोगों को एकजुट करके उस बुनियादी एकता की आपूर्ति की थी, जिनकी भाषा संस्कृत या फारसी से ली गई थी, और दक्षिण बोलने वाली द्रविड़ भाषाओं के लोग जो इस तरह से नहीं ली गई थीं। फिर, उच्च स्तर पर प्रशासन, उच्च शिक्षा, विधायिका, कानून अदालतें और व्यवसाय, सभी अंग्रेजी का उपयोग करते थे,

और सवाल यह था कि अंग्रेजी की जगह कौन सी भाषा लेनी चाहिए और कब?भारत के विभाजन तक, देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में हिंदुस्तानी इस क्षेत्र में थे। भारत के विभाजन के साथ हिंदुस्तानी का उद्देश्य खो गया था, हालांकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए खड़ा होना चाहिए और एक ऐसी भाषा पर दृढ़ रहना चाहिए जो लोगों के सबसे बड़े समूह द्वारा बोली जाती हो। हालाँकि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह आम तौर पर भारत के सभी हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, और हालाँकि लोगों के सबसे बड़े एकल समूह द्वारा बोली जाती थी, लेकिन उस समूह में भारत में बहुसंख्यक लोग नहीं थे। इसके अलावा, बंगाल में बंगाली, मद्रास में तमिल, पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य में मराठी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाएँ थीं जो बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती थीं और उन भाषाओं के लिए यह दावा किया जाता था कि वे हिंदी की तुलना में अधिक विकसित थीं। इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया था। संविधान सभा में हिंदी के नायक उस सर्वसम्मति के आधार को छोड़ने के लिए तैयार थे, जिस पर सभा ने काम किया था, लेकिन उनके चरम तरीकों ने प्रतिक्रिया को उकसाया और कुछ लोगों ने समर्थन किया।

उन्होंने पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस समय की सरकार बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संयम की सलाह दी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी से भारतीय भाषा में परिवर्तन करने में आने वाली कठिनाइयों के निकट संपर्क में लाया गया था। एक समय ऐसा प्रतीत होता था कि संविधान सभा में जो एकता थी, वह भाषा से संबंधित प्रावधानों पर टूट जाएगी। लेकिन अंतिम समय में, "मुंशी-अयंगर सूत्र" नामक एक समझौता सूत्र विकसित किया गया और इसे बिना असहमति के स्वीकार कर लिया गया। यह एक अधूरे मन का समझौता था, क्योंकि इसने किसी भी पक्ष को वह नहीं दिया जो वह चाहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को बताया कि उन्होंने हिंदी को स्वीकार नहीं किया होगा। आधिकारिक भाषा यदि स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था कि हिंदी हिंदुस्तानी को बाहर नहीं करती है, कि यह एक विद्वान मंडली की भाषा नहीं होनी चाहिए और हिंदी सभी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने वाली भारत की मिश्रित संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए। 15 साल की अवधि प्रदान की गई थी जिसके दौरान अंग्रेजी जारी रखनी थी लेकिन यह एक लचीली सीमा थी, क्योंकि संसद इसे बढ़ा सकती थी। अंकों पर लड़ाई को "भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप" के पक्ष में तय किया गया था-अरबी अंकों के लिए एक सौम्योक्ति, इस प्रावधान के साथ कि 15 वर्षों के बाद संसद कानून द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए अंकों के देवनागरी रूप के उपयोग का प्रावधान कर सकती है जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

 (ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधान-एक राष्ट्र की आधारशिला, नौवीं छाप, 2005, पृष्ठ 266 का संदर्भ दिया गया है।)

* (3 आरडी संस्करण, 2010 पीपी 1113-1114) पर

 (शिफमैन, हैरोल्ड। "भाषा नीति और भाषाई संस्कृति "। भाषा नीति का परिचयःसिद्धांत और विधि (2006):111-125)

1. श्री नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण; [(1975) 2 एससीसी 671]

14. समय-समय पर प्रयोग करने योग्य होने के लिए प्रदत्त शक्तियाँ। –(1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन द्वारा कोई शक्ति प्रदान की जाती है, तब तक जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है कि समय-समय पर अवसर की आवश्यकता के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) यह धारा जनवरी, 1887 के चौदहवें दिन या उसके बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों पर भी लागू होती है।